भारत सरकार

रेल मंत्रालय

राज्य सभा

20.03.2026 के

अतारांकित प्रश्न सं. 3319 का उत्तर

पंजाब में रेल परियोजनाओं में विलंब

3319 श्री हरभजन सिंह:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि वर्तमान में पंजाब में रेलवे की प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं में अत्यधिक विलंब हो रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो पंजाब में लंबित रेल परियोजनाओं के ब्यौरे सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके पूर्ण होने की समय-सीमा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय पंजाब में लंबित रेल परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाने के लिए कोई कदम उठा रहा है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): पंजाब राज्य में पूर्णत:/अंशत: आने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए किया गया बजट आवंटन निम्नानुसार है:

अवधि	परिव्यय
2009-14	225 करोड़ रुपए/वर्ष
2025-26	5,421 करोड़ रुपए (24 गुना से अधिक)

स्वीकृत की गई परियोजनाएं:

01.04.2025 की स्थिति के अनुसार, पंजाब राज्य में पूर्णतः/अंशतः आने वाली 21,926 करोड़ रुपए की लागत पर कुल 714 कि.मी. लंबाई की 09 परियोजनाएँ (04 नई लाइन और 05 दोहरीकरण) योजना/स्वीकृति/निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं, जिनमें से 115 कि.मी. की

लंबाई को कमीशन किया जा चुका है और मार्च, 2025 तक 8,079 करोड़ रुपए का व्यय उपगत किया गया है। सार निम्नानुसार है:-

कोटि	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई	कमीशन की गई लंबाई	मार्च, 2025 तक व्यय (करोड़ रुपए में)
नई लाइन	04	252 कि.मी.	64 कि.मी.	7,359
दोहरीकरण/बहुपथन	05	462 कि.मी.	51 कि.मी.	720
कुल	09	714 कि.मी.	115 कि.मी.	8,079

हाल ही में पूरी की गई परियोजनाएं:

पंजाब राज्य में पूर्णत:/अंशत: आने वाली हाल ही में पूरी की गईं कुछ परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	परियोजना	लागत (करोड़ रुपए में)
1	चक्की बैंक-भरौली दोहरीकरण (3 कि.मी.)	15
2	जाखल-मानसा दोहरीकरण (45 कि.मी.)	163
3	मीरथल-भंगाला ब्यास नदी दोहरीकरण (2.5 कि.मी.)	74
4	अंबाला-धप्पर-चंडीगढ़ दोहरीकरण (45 कि.मी.)	339
5	मानसा - बठिंडा दोहरीकरण (49 कि.मी.)	216
6	अमृतसर-छहरटा दोहरीकरण (7 कि.मी.)	31
7	जलंधर-पठानकोट-जम्मू तवी दोहरीकरण (209 कि.मी.)	850
8	रावी नदी पर पुल सहित कठुआ-माधोपुर पंजाब का दोहरीकरण (2.5 कि.मी.)	257
9	राजपुरा-बठिंडा दोहरीकरण (173 कि.मी.)	2459

चालू परियोजनाएं:

पंजाब राज्य में पूर्णत:/अंशतः आने वाली कुछ परियोजनाएं जिन्हें निम्नानुसार शुरू किया गया है:

क्र. सं.	परियोजना	लागत (करोड़ रुपए में)
1	नंगल डैम-तलवाड़ा-मुकेरियां नई लाइन (123 कि.मी.)	2018
2	भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी नई लाइन (63 कि.मी.)	6753
3	कादियां-ब्यास नई लाइन (40 कि.मी.)	842
4	फिरोजपुर-पट्टी नई लाइन (26 कि.मी.)	300
5	तलवंडी साबो के रास्ते रामा मंडी (रमन) - मौर मंडी (मौर)	154

	(29 कि.मी.) नई लाइन	
6	लुधियाना-किला रायपुर दोहरीकरण (19 कि.मी.)	238
7	लुधियाना-मुल्लनपुर दोहरीकरण (21 कि.मी.)	235
8	राजपुरा-मोहाली नई लाइन (18 कि.मी.)	443
9	राजपुरा बाईपास लाइन (14 कि.मी.)	412

कुछ प्रमुख परियोजनाएं जो भूमि अधिग्रहण के कारण विलंबित हैं, का ब्यौरा निम्नानुसार है: -

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कुल अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)	अधिगृहीत भूमि (हेक्टेयर में)	अधिगृहीत की जाने वाली शेष भूमि (हेक्टेयर में)
1	फिरोजपुर-पट्टी नई लाइन	166	0	166
2	अलाल-हिम्मताना कॉर्ड लाइन	20	0	20
3	कादियां-ब्यास नई लाइन	151	0	151
4	रामा मंडी (रमन) - तलवंडी साबो नई लाइन	85	0	85

फिरोजपुर-पट्टी नई लाइन (26 कि.मी.):

फिरोजपुर-पट्टी नई लाइन (26 कि.मी.) अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट एक महत्वपूर्ण परियोजना है जो पंजाब में स्थित है। इस परियोजना को वर्ष 2017-18 में 300 करोड़ रु. की लागत पर स्वीकृत किया गया था। इस परियोजना के लिए भूमि पंजाब राज्य सरकार द्वारा निशुल्कः सौंपी जानी थी। बहरहाल, राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण को पूरा नहीं किया जा सका। रणनीतिक कारणों से इस परियोजना के महत्व को ध्यान में रखते हुए, भूमि अधिग्रहण सहित केंद्रीय सरकार लागत पर इस नई रेल लाइन परियोजना को शुरू करने का विनिश्चय किया गया है। फिरोजपुर और तरन तारन जिलों में कुल 166 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। भूमि अधिग्रहण अग्रिम चरण पर है और अधिनिर्णय की घोषणा की गई है।

कादियां-ब्यास नई लाइन (39.6 कि.मी.):

कादियां-ब्यास (39.6 कि.मी.) नई रेल लाइन परियोजना को 2011-12 में स्वीकृत किया गया था। बहरहाल, कानून एवं व्यवस्था मुद्दों के कारण परियोजना को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। परियोजना को रोक दिया गया था। बहरहाल, इस परियोजना की आवश्यकता को देखते हुए, कार्य पुनः शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

भारत सरकार परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए तत्पर है, बहरहाल सफलता पंजाब सरकार के सहयोग पर निर्भर करती है।

रेल परियोजनाओं का पूरा होना विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जो निम्नानुसार हैं:

- राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण
- वानिकी स्वीकृति
- अतिलंघनकारी जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण
- विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां
- क्षेत्र की भू-वैज्ञानिक और स्थलाकृतिक परिस्थितियां
- परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति
- परियोजना स्थल विशेष के लिए एक वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या आदि

ये सभी कारक परियोजना/परियोजनाओं के समापन समय और लागत को प्रभावित करते हैं।

अमृत भारत स्टेशन:

भारतीय रेल ने दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है।

इस योजना में रेलवे स्टेशनों को बेहतर बनाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और उनका चरणों में कार्यान्वयन करना शामिल हैं। मास्टर प्लान बनाने में निम्नलिखित शामिल हैं:

- रेलवे स्टेशन और परिचलन क्षेत्रों तक पहुँच में सुधार
- रेलवे स्टेशन का शहर के दोनों तरफ के साथ एकीकरण
- रेलवे स्टेशन इमारत में सुधार
- प्रतीक्षालय, शौचालय, बैठने की व्यवस्था, वाटर-बूथों में सुधार
- यात्री यातायात के अनुरूप चौड़े ऊपरी पैदल पार पुल/एयर कॉन्कोर्स की व्यवस्था
- लिफ्ट/एस्केलेटर/रैम्प की व्यवस्था
- प्लेटफ़ॉर्म की सतह में सुधार/निर्माण और प्लेटफ़ॉर्म पर कवर की व्यवस्था
- 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क की व्यवस्था
- पार्किंग क्षेत्र, यातायात के विभिन्न साधनों का एकीकरण
- दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएँ
- बेहतर यात्री सूचना प्रणाली
- प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर आवश्यकता को देखते हुए एक्ज़ीक्यूटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए निर्दिष्ट स्थान, भूसुदर्शनीकरण आदि की व्यवस्था।

इस योजना में आवश्यकता, चरणबद्धता एवं व्यवहार्यता के अनुसार दीर्घकालिक और पर्यावरण अनुकूल समाधान; गिट्टी रहित पटरियों की व्यवस्था आदि और दीर्घावधि में रेलवे स्टेशन पर सिटी सेन्टरों के निर्माण की परिकल्पना भी की गई है।

अभी तक, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकास के लिए 1338 रेलवे स्टेशनों को चिह्नित किया गया है जिनमें से 30 स्टेशन पंजाब में हैं। पंजाब में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकास हेतु चिह्नित किए गए स्टेशनों के नाम इस प्रकार हैं:

राज्य	स्टेशनों की संख्या	स्टेशनों के नाम
पंजाब	30	अबोहर, अमृतसर, आनंदपुर साहिब, ब्यास, बठिंडा जंक्शन, ढंडारी कलां, धुरी, फाजिल्का, फिरोजपुर कैंट, गुरदासपुर, होशियारपुर, जलंधर छावनी जंक्शन, जलंधर सिटी जंक्शन, कपूरथला, कोटकपूरा जंक्शन, लुधियाना जंक्शन, मालेरकोटला, मानसा, मोगा, मुक्तसर, नांगल डैम, पठानकोट कैंट, पठानकोट जंक्शन, पटियाला, फगवाड़ा जंक्शन, फिल्लौर जंक्शन, रूप नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर मोहाली, संगरूर, सरहिंद

स्टेशन जहां कार्य पूरा हो चुका है:

पंजाब राज्य में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों पर विकास कार्य अच्छी गति से शुरू किए गए हैं। अब तक पंजाब में 3 स्टेशनों के कार्य पूरे किए गए हैं। पंजाब राज्य में पूरे किए गए स्टेशनों का नाम निम्नानुसार है:

राज्य	स्टेशनों की संख्या	स्टेशनों के नाम
पंजाब	3	आंनदपुर साहिब, मुक्तसर और साहिबजादा अजीत सिंह नगर मोहाली

अन्य स्टेशनों पर भी विकास के लिए गतिविधियों को तीव्र गति से शुरू किया गया है और कुछ स्टेशनों की प्रगति निम्नानुसार हैः-

- **सरहिंद स्टेशन:** स्टेशन भवन में सुधार, प्रवेश प्रांगण, शौचालय सुविधा के साथ वातानुकूलित प्रतीक्षालय, द्वितीय श्रेणी प्रतीक्षालय में सुधार, शौचालय ब्लॉक, परिचलन क्षेत्र, पार्किंग, प्रवेश/निकास गेट, प्रकाश और संसूचक का कार्य पूरा कर लिया गया है। लिफ्ट का कार्य और 12 मी. फुट ओवर ब्रिज का कार्य शुरू किया गया है।

- **गुरदासपुर स्टेशन:** स्टेशन भवन, प्लेटफ़ॉर्म शेल्टर, प्लेटफ़ॉर्म की सतह में सुधार, प्रतीक्षालय, शौचालय, परिचलन क्षेत्र, प्रांगण और प्रकाश व्यवस्था का कार्य पूरा कर लिया गया है। नए प्लेटफार्म नं. 2, बुकिंग एवं प्रतीक्षालय, परिचलन क्षेत्र, पार्किंग, मुख्य प्रवेश और दूसरी ओर प्रवेश/निकास गेट और 12 मी. फुट ओवर ब्रिज का कार्य शुरू किया गया है।

- **पटियाला स्टेशन:** स्टेशन भवन, प्रवेश प्रांगण, प्लेटफार्म शेल्टर, प्रतीक्षालय, विश्रामालय, शौचालय, परिचलन क्षेत्र, पार्किंग, प्रवेश/निकास गेट और संसूचक का सुधार कार्य पूरा कर लिया गया है। प्लेटफार्म की सतह, दूसरे प्रवेश द्वार का विकास, लिफ्ट और 12 मीटर फुट ओवर ब्रिज का कार्य शुरू किया गया है।

- **संगरूर स्टेशन:** स्टेशन भवन, प्रवेश प्रांगण, प्लेटफॉर्म शेल्टर, प्रतीक्षालय, शौचालय ब्लॉक, परिचलन क्षेत्र, पार्किंग, प्रवेश/निकास गेट और संसूचक के सुधार के कार्य पूरे किए गए हैं। प्लेटफॉर्म नं. 1 पर प्लेटफॉर्म सतहीकरण, लिफ्ट और 4.8 मीटर फुट ओवर ब्रिज का कार्य शुरू किया गया है।

इसके अलावा, भारतीय रेल में स्टेशनों का विकास/पुनर्विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इस संबंध में कार्य सापेक्ष प्राथमिकता और धन की उपलब्धता के अध्यधीन आवश्यकता के अनुसार शुरू किए जाते हैं। स्टेशन का विकास/पुनर्विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण स्टेशन की कोटि/अवस्था/यातायात की सम्हलाई आदि के आधार पर क्रियान्वित किया जाता है।

रेलवे स्टेशनों का विकास/उन्नयन जटिल स्वरूप का होता है जिसमें यात्रियों और रेलगाड़ियों की संरक्षा अंतर्ग्रस्त होती है और इसके लिए दमकल विभाग की स्वीकृति, धरोहर, पेड़ों की कटाई, विमानपत्तन संबंधी स्वीकृति इत्यादि जैसी विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियों की आवश्यकता होती है। इनकी प्रगति जनोपयोगी सेवाओं (जिनमें जल/सीवेज लाइन, ऑप्टिकल फाइबर केबल, गैस पाइप लाइन, पावर/सिगनल केबल इत्यादि शामिल हैं) अतिलंघनों को स्थानांतरित करने, यात्री संचलन को बाधित किए बिना रेलगाड़ियों के परिचालन, रेलपथ एवं उच्च वोल्टेज बिजली लाइनों के नजदीक किए जाने वाले कार्यों के कारण गति प्रतिबंध आदि जैसी ब्राउन फील्ड संबंधी चुनौतियों के कारण भी प्रभावित होती है और ये कारक कार्य के समापन समय को प्रभावित करते हैं।

सामान्यतः अमृत भारत स्टेशन योजना सहित अन्य योजनाओं के अंतर्गत स्टेशनों के विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण का वित्तपोषण योजना शीर्ष-53 'ग्राहक सुविधाएँ' के अंतर्गत किया जाता है। योजना शीर्ष-53 के अंतर्गत स्टेशनों के आबंटन और व्यय का ब्यौरा क्षेत्रीय रेल-वार रखा जाता है, न कि कार्य-वार या रेलवे स्टेशन-वार या राज्य-वार। पंजाब दो रेलवे जोनों, अर्थात् उत्तर रेलवे और उत्तर पश्चिम रेलवे के अधिकार क्षेत्र में आता है। इन जोनों के लिए, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 2390 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है, जिसमें से 2379 करोड़ रुपये का व्यय (फरवरी 2026 तक) उपगत किया जा चुका है।

ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल:

भारतीय रेल में ऊपरी/निचले सड़क पुलों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति और निष्पादन एक सतत् और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसे निर्माण कार्यों की प्राथमिकता का निर्धारण और शुरुआत गाड़ी परिचालन में संरक्षा और गतिशीलता पर उनके प्रभाव तथा सड़क उपयोगकर्ताओं पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर किया जाता है।

2004-14 की तुलना में 2014-26 (जनवरी, 2026 तक) की अवधि के दौरान भारतीय रेल पर निर्मित ऊपरी/निचले सड़क पुलों की संख्या निम्नानुसार है:

अवधि	निर्मित ऊपरी/निचले सड़क पुल
2004-14	4,148 अदद
2014-26 (जनवरी 2026 तक)	14,024 अदद (पंजाब राज्य में 434 अदद ऊपरी/निचले सड़क पुल सहित)

01.02.2026 तक की स्थिति के अनुसार, पंजाब राज्य में 1848 करोड़ रुपए की लागत पर 120 अदद ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुलों सहित भारतीय रेल पर 1,14,196 करोड़ रुपए की लागत पर 4802 अदद ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल स्वीकृत किए गए हैं, जो योजना और निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं।

18 अदद ऊपरी सड़क पुल/निचले पुल पंजाब सरकार के कारण विलंबित हैं। जिनका ब्यौरा निम्नानुसार हैं:

कारण	ऊपरी/निचले सड़क पुल (अदद में)
राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण में विलंब	10
राज्य प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रतीक्षा है	07
उपयोगिताओं का स्थानांतरण	01

किसी ऊपरी/निचले सड़क पुल के कार्य को पूरा करना, पहुंच मार्ग का संरेखण निर्धारित करने, सामान्य आरेखण व्यवस्था के अनुमोदन, भूमि अधिग्रहण, अतिक्रमण हटाने, अतिलंघनकारी जनोपयोगी सेवाओं के स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, परियोजना/कार्य स्थलों के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति, जलवायु संबंधी परिस्थितियों आदि के कारण परियोजना विशिष्ट/कार्य स्थल के लिए वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। ये सभी कारक परियोजनाओं/निर्माण कार्यों के समापन समय को प्रभावित करते हैं।

इसके अलावा, रेलवे ने कार्यों की प्रगति में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

i. सुचारू निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए सामान्य व्यवस्था आरेखण (जीएडी) को अंतिम रूप देने से पहले संबंधित राज्य सरकार/सड़क स्वामित्व प्राधिकरण के साथ संयुक्त सर्वेक्षण किया जाता है।
ii. ऊपरी/निचले सड़क पुलों के निर्माण कार्यों से संबंधित विभिन्न मुद्दों को सुलझाने के लिए रेलवे और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ आवधिक बैठकें की जाती हैं।
iii. डिजाइन के अनुमोदन के दौरान विलंब से बचने के लिए रेलवे के हिस्से में स्पैन के विभिन्न संयोजनों, तिर्यकता और सड़क की चौड़ाई हेतु अधिसंरचना आरेखणों का मानकीकरण किया गया है। इसे सार-संग्रह के रूप में जारी किया गया है, जिसे सर्वत्र रेल लाइनों पर ऊपरी सड़क पुल निर्माण के लिए त्वरित योजना बनाने हेतु सीधे अपनाया जा सकता है।

******